संपादकीय जागरण

रविवार, 4 नवंबर, 2018 : कार्तिक कृष्ण 12 वि. 2075

अविद्या से उत्पन्न अज्ञान ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है

चुनावी अतिवाद

यह चिंताजनक है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमलों का अंदेशा बढ़ गया है। चूंकि इस अंदेशे का एक बड़ा कारण राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव हैं इसलिए यह अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया के लिए नक्सली एक बड़ा खतरा बन गए हैं। विडंबना यह है कि तथाकथित बुद्धिजीवियों का एक गुट लोकतंत्र को नष्ट करने पर आमादा इन नक्सलियों का हितैषी बना हुआ है। वह उन्हें न केवल वैचारिक खुराक देता है, बल्कि उनके हितों को पूरा करने के लिए दबे-छिपे ढंग से काम भी करता है। यह भी एक विडंबना ही थी कि पिछले दिनों जब कुछ ऐसे ही संदिग्ध तत्व गिरफ्तार किए गए तो न केवल आसमान सिर पर उठा लिया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी प्रभाव में लेने की कोशिश की गई। इस सबसे यही प्रकट हुआ कि अतिवादी तत्वों के साथ-साथ उनके शहरी समर्थकों से भी सख्ती से निपटने की जरूरत है। यह पहली बार नहीं जब चुनावी माहौल में नक्सली अपने मजबूत ठौर-ठिकानों में हिंसक गतिविधियां तेज करते दिख रहे हैं। वे यह कारनामा पहले भी करते रहे हैं। यही कारण है कि नक्सल प्रभावित राज्यों में चुनाव के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है। यह शुभ संकेत नहीं कि छत्तीसगढ़ में चौकसी बढ़ाए जाने के बावजूद नक्सली सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक के बाद एक दो हमले किए। पहले हमले में सीआरपीएफ के चार जवान शहीद हो गए और दूसरे में दो पुलिस कर्मियों समेत दूरदर्शन के एक कैमरामैन की जान चली गई। बाद में नक्सलियों ने कैमरामैन की मौत पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए यह सफाई दी कि उनका इरादा पत्रकार को मारने का नहीं था, लेकिन सच तो यही है कि वे यह नहीं चाह रहे थे कि देश को ऐसी कोई खबर जाए कि छत्तीसगढ़ के गरीब ग्रामीण मतदान के लिए उत्साहित हैं।

जैसे आज छत्तीसगढ़ में नक्सली चुनाव प्रक्रिया को छिन्न-भिन्न करना चाह रहे हैं वैसे ही देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी चुनावों के दौरान किस्म-किस्म के अतिवादी तत्व सिर उठा लेते हैं। कई बार तो स्थानीय निकायों के चुनावों के मौके पर भी ऐसा होता है। राजनीतिक दलों को न केवल इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर चुनावी माहौल में अतिवादी तत्व सिर क्यों उठा लेते हैं, बल्कि खुद भी चुनावी आक्रामकता को मर्यादित करना सीखना चाहिए। यह ठीक नहीं कि चुनावों के दौरान एक-दूसरे पर अभद्र आरोप, निराधार लांछन और शालीनता को तज कर की जाने वाली तू तू-मैं मैं अब आम हो गई है। चूंकि इससे बचने के लिए कहीं कोई कोशिश नहीं हो रही इसलिए अब राजनीतिक दल छल-कपट का सहारा लेने और अवसरवाद का जुगुप्सा भरा प्रदर्शन करने में भी संकोच नहीं करते। यह और कुछ नहीं, एक किस्म का सियासी अतिवाद ही है। यह भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। आखिर राजनीतिक दलों को मर्यादित तरीके से चुनाव लड़ने में क्या परेशानी है? वे एक ओर तो यह कहते हैं कि जनता बहुत समझदार है और दूसरी ओर ऐसा आचरण करते हैं मानो उसमें कोई समझ ही न हो।

कठिन आवागमन

प्रदेश के अधिकतर शहरों से दिल्ली, मुंबई सहित सभी गंतव्यों के लिए परिवहन सुविधाओं का अभाव त्योहारों का मजा किरकिरा कर देता है। जगजाहिर है कि शिक्षा और रोजगार के लिए प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और कई अन्य राज्यों में रहते हैं। स्वाभाविक रूप से ये लोग दिवाली और अन्य बड़े पर्वों पर अपने घर आते हैं यद्यपि ट्रेनों, बसों और वायुयान में सीटों का अभाव इन लोगों के लिए बड़ी समस्या बन जाता है। वायुयान में तो ऐसे अवसरों पर किराया भी कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग मन मसोसकर घर आने का इरादा छोड़ देते हैं और उन्हें परिवार से दूर रहकर त्योहार मनाना पड़ता है। यह स्थिति त्रासद है। विडंबना है कि हर साल और हर त्योहार पर होने वाली इस कठिनाई से निपटने के लिए संबंधित विभाग मुकम्मल इंतजाम नहीं कर पाते। अधिकतर लोग दिवाली का त्योहार परिवार और मित्रों के साथ मनाना चाहते हैं। किसी तरह घर पहुंच तो रहे हैं, पर इनकी दिवाली वापसी की चिंता में ही गुजरना तय है। ट्रेनों में कई दिन पहले ही नो रूम की स्थिति बन चुकी है। यही हाल लंबी दूरी वाली बसों का भी है। जहां तक वायुयान की बात है, उनकी सीटें सीमित होती हैं। ऊपर से किराया भी अधिक हो गया है। रेलवे ने त्योहार के मद्देनजर अतिरिक्त ट्रेनों और कोचों की जो व्यवस्था की है, वह ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। रेल और परिवहन मंत्रालयों को मौजूदा हालात की अविलंब समीक्षा करके यात्रियों की सुविधा के लिए युद्धस्तर पर इंतजाम करना चाहिए।

जिन विमान कंपनियों ने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर किराया अनाप-शनाप बढ़ा दिया है, उनकी भी नकेल कसी जानी चाहिए

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आगामी आम चुनावों में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बन सकता है?

आज का सवाल
क्या अदालती फैसलों के हिंदी में अनुवाद से लोगों में न्यायिक समझ बढ़ेगी?

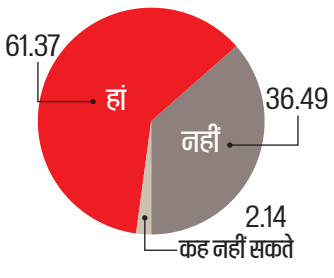

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

फिर अधर में अयोध्या विवाद

संजय गुप्त

राम मंदिर निर्माण के आकांक्षी लोगों और संगठनों की बेचैनी समझ आती है, लेकिन इसमें संदेह है कि अयोध्या विवाद के समाधान के लिए अध्यादेश लाने से बात बनेगी

अयोध्या में राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के साथ-साथ संत समाज ने मोदी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। उनकी मांग है कि उच्चतम न्यायालय की ओर से अयोध्या मामले की सुनवाई टालने के बाद केंद्र सरकार कानून बनाकर या अध्यादेश लाकर राम मंदिर निर्माण की राह साफ करे। हिंदुओं को नैतिक रूप से सबल करके वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण करने के उद्देश्य से स्थापित संघ के लिए अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का मंदिर निर्माण एक महत्वपूर्ण मसला है। वह विवादित ढांचा गिराए जाने के पहले से ही मंदिर निर्माण के लिए आंदोलनरत है। यह आंदोलन 1992 में चरम पर पहुंचा और कारसेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। अयोध्या ढांचा गिरने का राष्ट्र पर जैसा असर पड़ा उसकी सामाजिक और राजनीतिक टीस आज तक महसूस की जा रही है। जो लोग मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे हैं वे इस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं कि अगर अयोध्या में राम के जन्म स्थान पर मंदिर नहीं बनेगा तो और कहां बनेगा? आखिर जब इसके पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं कि बाबर के सेनापति मीर बकी ने राम मंदिर को ढहाकर मस्जिद बनवाई थी तब फिर वहां मस्जिद बनाने के लिए जिद क्यों? यह हैरानी की बात है कि इस जिद को कुछ राजनीतिक और सामाजिक संगठन हवा देने में लगे हुए हैं और इसी कारण वे अयोध्या के विवादित स्थल से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों की अनदेखी कर रहे हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि मंदिर निर्माण के विरोध का एक बड़ा कारण वोट बैंक की राजनीति है। इसी राजनीति से ग्रस्त होकर कांग्रेस और अन्य दलों ने अयोध्या विवाद को सुलझाने की कोई ठोस पहल नहीं की। धीरे-धीरे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। इस मुद्दे को जब संघ और भाजपा ने अपने एजेंडे में लिया तो विपक्षी दलों ने मंदिर निर्माण के अपने विरोध को और तेज कर दिया। यह मसला उनके लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का हथियार बन गया। ऐसे ही हालात में 1989 में लालकृष्ण आडवाणी की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू की गई रथयात्रा ने अयोध्या मसले को सतह पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मंदिर मुद्दे पर बनी लहर के कारण केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग की सरकार भी बनी, लेकिन गठबंधन राजनीति की मजबूरी के कारण उसे इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में रखना पड़ा। जब 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अयोध्या विवाद में राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला दिया तो ऐसा लगा कि सदियों की प्रतीक्षा पूरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। उम्मीद यह की जा रही थी कि वह जल्द ही अपना निर्णय सुना देगा, लेकिन सात साल बीत गए और फैसला लंबित है।

वर्तमान में किसी के लिए भी यह कहना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब

अवधेश राजपूत

आएगा? इस मामले की जल्द सुनवाई संबंधी याचिका पेश होने पर एक समय सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक रवैया अवश्य अपनाया, लेकिन उसके सामने यह एक याचिका पेश कर दी गई कि अयोध्या मामले की सुनवाई के पहले 1994 के उस फैसले पर विचार हो जिसमें कहा गया था कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर विचार करने के बाद यह पाया कि उक्त मामले का अयोध्या मसले से कोई लेना-देना नहीं। इसके बाद यह माना गया कि अब इस मामले की दिन-प्रतिदिन सुनवाई का रास्ता साफ हो गया, लेकिन बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या मसले की सुनवाई के लिए नई पीठ बनाने के आदेश देते हुए यह कहा कि यही पीठ जनवरी में बताएगी कि सुनवाई कब होगी तो फिर से निराशा फैल गई। निराशा के इसी माहौल में यह मांग तेज हुई है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कानून का सहारा लिया जाए। एक ओर जहां संघ कानून बनाने पर जोर दे रहा है वहीं भाजपा के राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए निजी बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं। शायद इसका उद्देश्य विपक्षी दलों के रुख-रवैये की थाह लेना है। देखना है कि विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस इस निजी बिल पर क्या रुख अपनाती है?

इधर राहुल गांधी अपने को शिवभक्त बताते और मंदिर-मंदिर जाते दिख रहे हैं। इस बदलाव का कारण कांग्रेस को यह बात समझ आना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उसे नुकसान पहुंचा रही है। राहुल गांधी इसीलिए नरम हिंदुत्व की राह पर हैं, लेकिन यह कहना कठिन है कि वह राम मंदिर मसले पर क्या रुख अपनाएंगे? अगर वह इस या उस बहाने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की किसी पहल का विरोध करते हैं तो इससे हिंदुत्व के प्रति उनके अनुराग को लेकर नए सिरे से सवाल उठना तय है। आरएसएस तो यही चाहेगा कि न केवल कांग्रेस, बल्कि अन्य विपक्षी दल राम मंदिर पर अपना नजरिया साफ करें। इस रणनीति में हर्ज नहीं, क्योंकि यही विपक्षी दल रह-रह कर भाजपा पर यह तंज भी कसते रहते हैं कि वह राम को भूल गई। इसके बावजूद यदि आरएसएस मोदी सरकार पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए अध्यादेश लाने का दबाव बनाता है तो इससे जनता को यही संदेश जाएगा कि आम चुनाव के पहले माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। यह संदेश इसलिए भी जाएगा, क्योंकि बीते चार सालों में संघ ने राम मंदिर को लेकर ऐसी व्यग्रता नहीं दिखाई।

मौजूदा माहौल में बेहतर यही होगा कि संघ के साथ अन्य सामाजिक एवं धार्मिक संगठन और विशेषकर मुस्लिम संगठन इसके लिए आगे आएं कि अयोध्या विवाद आपसी सहमति से सुलझे और वहां राम मंदिर बने। ऐसी पहल इसलिए होनी चाहिए, क्योंकि राम सबके हैं और राम के बगैर भारत की कल्पना करना मुश्किल है। मुस्लिम पक्ष यह स्वतः समझे तो सबसे बेहतर कि अयोध्या राम के लिए जानी जाती है और वहां बनी कथित बाबरी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इस्लाम के उसूल यही कहते हैं कि किसी दूसरे की जगह या फिर विवादित स्थल पर मस्जिद बनाना सही नहीं, लेकिन मुस्लिम संगठनों को यह बात इसलिए नहीं समझाई जाती, क्योंकि विपक्षी दल उन्हें बरगलाकर वोट बैंक की राजनीति करना बेहतर समझ रहे हैं। इसी राजनीति के कारण अयोध्या विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। चूंकि अयोध्या विवाद की सुनवाई टलने से लोगों को गहरी निराशा हुई है इसलिए आरएसएस और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आकांक्षी आम लोगों और संगठनों की बेचैनी समझ आती है, लेकिन इसमें संदेह है कि अयोध्या विवाद के समाधान के लिए अध्यादेश लाने से बात बनेगी। शायद यही कारण है कि सरकार इस मसले पर किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। आरएसएस को उसके संकेत समझने चाहिए।

response@jagran.com

लोकतंत्र का मायाजाल

हास्य-व्यंग्य

बहुत वर्ष हुए इंद्रप्रस्थ में महाराजा चक्रम नाम के एक महाप्रतापी राजा हुए। पूर्व के भ्रष्टाचारी और अकर्मण्य शासक को हटाकर जब महाराज सत्ता पर आसीन हुए तो उन्होंने पुराने शासक के काल में पनपे भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाई का प्रजा को वचन दिया और नगर कोतवाल को आदेश दिया कि बिना घूस के कार्रवाई की जाए। यह तो वही हुआ कि मानो बिना सूरज के भोर हो, बिना पूजा के प्रसाद हो, बिना तीर्थ के पुण्य मिले, बिना मृत्यु के स्वर्ग मिले और बिना जनमत के सत्ता मिले। कोतवाल साहब निर्देश प्राप्त करते ही चिंतित हुए, विचलित हुए और मन ही मन प्रतापी सम्राट के लिए कुछ पुलिस सुलभ संज्ञाओं का प्रयोग किया और पुरानी प्रीपेड निष्ठा को त्यागकर सवैतनिक कर्मचारी की सार्वभौमिक निष्क्रियता के साथ, कुर्सी के पृष्ठ भाग पर सफेद तौलिये को स्थापित करने की शासकीय प्रक्रिया के साथ कार्य में संलग्न हुए।

पहला मामला सहसा ही जागरूक हुई जनता के प्रभाव मे राजगुरु की अदालत मे पहुंचा। आह, राजगुरु का विराट व्यक्तित्व और उससे भी विराट तोंद और इस महान कालजयी व्यक्ति की महान काया पर निर्भर राष्ट्रीय नैतिकता। साक्ष्यों को निहारने के पश्चात नगर-न्यायाधीश बोले तो भक्तिभाव में लीन जनता को ऐसा भान हुआ मानो देव वाणी हुई। प्रभु बोले- ताजा लाओ। इससे पहले कि नाचती हुई अभिनेत्री चाय का पैकेट लेकर और अदालत के बाहर सब्जी का ठेला लगाने वाला रामस्वरूप ताजा धनिये की गड्डी महामहिम तक पहुंचाए, महामहिम ने स्पष्ट किया कि वह ताजे साक्ष्यों की ही बात कर रहे हैं। अपराध भले ही दशकों पुराना हो, गुरुवर को साक्ष्य ताजा और पौष्टिक ही स्वीकार्य हैं।

कोतवाल मुकदमे लाता रहा, कहीं साक्ष्य बासी निकल गए, कहीं अपराध ही बासी निकल गए। स्वास्थ्य-सजग

साकेत सूर्येश

सत्ता, प्रशासन और शासन के भ्रमजाल को ही लोकतंत्र कहते है, जिसमें गति का बोध काल्पनिक होता है, बदलता कुछ नहीं

न्यायालय को अपराध और साक्ष्य दोनों ही बासी स्वीकार्य नहीं थे। जनता अपनी जनतंत्र-सुलभ निराशा में लौटने लगी तो चक्रवर्ती सम्राट चिंतित हो गए। सम्राट ने सलाहकारों की गोष्ठी बुलाकर कहा कि देश में व्यवस्था पुनः अपनी पूर्ववत स्थिति में लौट रही है। विद्वानों ने कहा कि यह तो लोकतंत्र का मूल स्वभाव है। क्षणिक उत्साह के पश्चात पूर्ववत स्थिति में सत्ता के लौट जाने के भाव को ही आधुनिक हरियाणा रोडवेज की बसों पर यह लिखकर दर्शाया जाता है कि 'यह तो ऐसे ही चलेगी।' बहरहाल सम्राट चक्रम के समय न तो हरियाणा रोडवेज थी और न ही बसें, सम्राट थे अति उत्साही, सो उन्होंने राजगुरु से ही इसका समाधान पूछा। राजगुरु महान थे। राजगुरु इसलिए महान थे, क्योंकि उनके पिता भी महान थे और पितामह भी।

राजगुरु ने कहा कि, 'हे राजन, नगर कोतवाल का कार्य कठिन मामलों में गहन पड़ताल कर साक्ष्य एकत्रित करना नहीं होता। उसका अधिकार क्षेत्र केले के ठेले वालों से सप्ताह दर सप्ताह केले लेने तक सीमित है। इसके लिए आपको गुप्तचर विभाग की मदद लेनी चाहिए। होते तो इसमें भी व्यक्ति पुलिस विभाग के होते हैं, किंतु केले के ठेलों से अधिक परिष्कृत होते हैं और केले के अलावा अन्य फल और सब्जियां अपने घरों के अलावा हमारे आपको घरों तक पहुंचाने में सक्षम हैं।

राजा चक्रम बोले-किंतु वे हैं कहां आजकल?

प्रभु ने आंखें बंद कर के ध्यान लगाया और बोले- हे देव, गुप्तचर विभाग एक जिन्न है जो पूर्वजन्म में तोते के रूप में सत्ताधारियो के पिंजरे में था। शासन के निर्देशानुसार वह संगीत लहरियां छेड़कर पूर्व साम्राज्ञी का मनोरंजन किया करता था। वर्तमान में सत्ता के द्वारा स्वायत्त घोषित किए जाने के बाद इसने बहुत दूर नीरव श्मशान में आवास बनाया है। वहीं एक प्राचीन पीपल पर उलूक अवतार मे यह उलटा लटका हुआ है और पीपल के नीचे के तालाब में अपने ही प्रतिबिंब को मुंह चिढ़ाकर मखौल करता रहता है। आपके पूर्ण चंद्र की रात्रि में इसे वापस शहर में लाना होगा ताकि यह गिद्ध रूप में आकर अपना कर्तव्य पालन कर सके।

महाराज उठ खड़े हुए।

सलाहकारों ने रोका। बोले- महाराज, वहां एक मायावी वन है जहां वह उलूक लटका हुआ है। आप गलत उलूक को न पकड़ लाएं, अन्यथा वह पिंजरे मे बंद तोता बनकर गीत ही सुनाएगा, गिद्ध दृष्टि से राष्ट्र रक्षा न कर सकेगा।

महाराज चक्रम मुस्कुराए- वत्स, माया का क्षेत्र वन तक ही सीमित नहीं है। जिसे तुम मैं समझ रहे हो मैं कहां है। सत्ता तो माया के प्रभाव में बस चलती हुई ही जान पड़ रही है, वास्तविक महाराज चक्रम तो त्रिलोक विजय के अश्वमेध का अश्व लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य भटक रहे हैं। सत्ता, प्रशासन और शासन के इसी भ्रमजाल को लोकतंत्र कहते है, जिसमें गति का बोध काल्पनिक होता है और प्रत्येक परिवर्तन के पर्दे के पीछे सब स्थिर, स्थाई एवं अपरिवर्तनीय रहता है। प्रत्येक पटाक्षेप के उपरांत जब पर्दा उठता है तो कलाकार बदलते हैं, पटकथा के साथ ही पात्र वही रहते हैं। उलूक अपने प्रतिबिंब से युद्धरत रहते हैं, तोता गाता रहता है, सब कुछ वैसा ही रहता है जैसा था।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | कारोबारी सुगमता पर विश्व बैंक की रैंकिंग

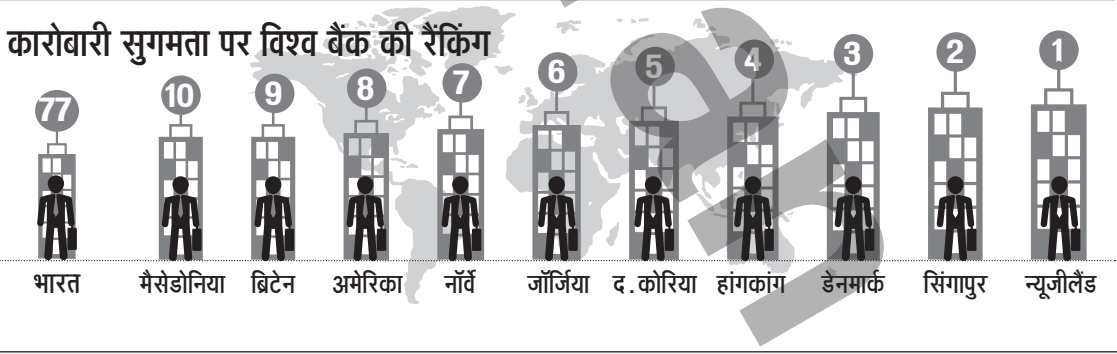

ऊर्जा

जीवन के द्वंद्व

द्वंद्व का आशय विरोधाभास पूर्ण स्थितियां हैं। अधिकांश लोग ऊहापोह में अपना सुख-चैन गंवा बैठते हैं। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन प्रायः सुख की यही कामना उनके दुखों का मूल कारण बन जाती है। इसी उपक्रम में वह कृत्रिमता का आवरण ओढ़ लेता है जो कि एक खतरनाक स्थिति है। मन भयाक्रांत रहता है कि किसी दिन वास्तविकता प्रकट हुई तब क्या होगा? अक्सर यह भी देखने में आता है कि लोग दूसरों को कोसते रहते हैं। दूसरों के मन में क्या चल रहा है, इसका अनुमान लगाना कठिन है, फिर भी व्यक्ति उसके लिए परेशान रहता है। दूसरों की संपन्नता पर वह स्वयं कुपित होकर अपने लिए परेशानियां आमंत्रित कर लेता है। दूसरों के धनसंग्रह में उसे खोट दिखता है जबकि अपनी काली कमाई के लिए वह भगवान का सहारा ले लेता है। काली कमाई का परिणाम काला ही होगा। जीवन में भी काले धन का परिणाम श्वेत करना असंभव है। इससे सबसे पहले आपका दृष्टिकोण ही कलुषित होता है। धर्मग्रंथों में निकृष्ट लोगों में प्रायः त्रेतायुग के रावण तथा द्वापर में दुर्योधन का जिक्र आता है।

रावण ज्ञानी था। इसके बावजूद उसकी दृष्टि-सोच दूषित थी। उसका अंत बुरा हुआ। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में सभी परिजनों सहित मारे गए दुर्योधन का नाम तो सुयोधन था, लेकिन उसकी दृष्टि और सोच दूषित हुई तो उसकी प्रवृत्तियां बदल गईं। उससे जब कभी पितामह भीष्म अपनी प्रवृत्ति बदलने के लिए कहते तथा उसके खतरनाक परिणामों के बारे में बताते तो वह यही कहता था कि वह जानता है कि परिणाम भयानक होंगे, लेकिन अपनी सोच और प्रवृत्तियों को वह नहीं बदल पा रहा है। भौतिक वैभव का लालच उसे गलत काम के लिए प्रेरित करता है। व्यक्ति सिर्फ अपने मन को द्वंद्व से मुक्त रखे तो जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाइयां भले आ जाएं, लेकिन वह तमाम अनावश्यक परेशानियों से मुक्त रहेगा। जिन रास्तों से भूख, नींद, चैन गायब हो, उन रास्तों पर एक कदम नहीं चलना चाहिए। गलत तरीके से प्राप्त भौतिक उपलब्धियों से परिवार के संस्कार भी इसलिए बिगड़ते हैं, क्योंकि इन उपलब्धियों के पीछे भागने वाला अपने बचाव के उपायों में ही उलझा रहता है और अपने आश्रितों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाता।

सलिल पांडेय

अढिया के लिए सब कुछ बढ़िया नहीं

देश के सबसे ताकतवर नौकरशाहों में शुमार किए जाने वाले हसमुख अढिया का सेवाविस्तार सत्ता के गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। बजट की तैयारियों के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खुद अढिया को सेवाविस्तार दिए जाने की सिफारिश की थी। यही नहीं, गुजरात कैडर के अधिकारी अढिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी काफी करीब माने जाते रहे हैं और योग को लेकर दोनों के लगाव की भी चर्चा होती रही है। ऐसे में उन्हें सेवाविस्तार मिलना तय माना जा रहा था, लेकिन बड़े नौकरशाहों के बीच चल रही कानाफूसी के अनुसार अढिया का सबकुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। चर्चा तो यहां तक है कि पीएमओ ने उन्हें सेवाविस्तार देने से दो-टूक इन्कार कर दिया। यही नहीं, पीएमओ उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किसी नई जगह भी भेजने को तैयार नहीं है। अढिया 30 नवंबर को सेवानिवृत हो रहे हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें वापस गुजरात जाने और योग के अपने शौक को पूरा करने के अलावा कोई उपाय नहीं है।

जुगाड़ की नौकरशाही

नौकरशाही भी सबके बस की बात नहीं है। दिल्ली में बने रहने के लिए नौकरशाहों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे ही एक नौकरशाह आजकल एक केंद्रीय मंत्री के पीएस के तौर पर काम कर रहे हैं। आमतौर पर मंत्रियों के पीएस निदेशक स्तर के अधिकारी होते हैं, लेकिन ये साहब अब संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी बन चुके हैं। बावजूद इसके इनकी दिलचस्पी पीएस बने रहने में ही है। वजह इनकी पत्नी हैं जो विदेश सेवा में कार्यरत हैं और दिल्ली में ही तैनात हैं। लिहाजा वह भी नई नियुक्ति लेने से कतरा रहे हैं कि कहीं दिल्ली से बाहर न जाना पड़े। इन स्थितियों में अब प्रधानमंत्री के निजी सचिव के बाद संभवतः केवल एक यही अधिकारी हैं जो संयुक्त सचिव स्तर के होने के बावजूद बतौर पीएस काम कर रहे हैं।

राजरंग

मामा के बच्चों का मामा

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के रिश्तेदार संजय सिंह के कांग्रेस में शामिल होते ही राजनीतिक जुमलों की जैसे बरसात शुरू हो गई। संजय ने कांग्रेस की वजह भाजपा में परिवारवाद को बताया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वह खुद कांग्रेस में इसीलिए आए, क्योंकि भाजपा ने परिवारवाद की मुखालफत करते हुए उन्हें टिकट देने से इन्कार कर दिया। लेकिन अब वह खुद पलटकर पार्टी पर यही आरोप लगा रहे हैं। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रदेश के राजनीतिक हलकों में यह जुमला चल निकला है 'मामा के बच्चों का मामा तो गियो।'

'चरण वंदना' वाली राजनीति

राजनीतिक पार्टियों में नेताओं के बढ़ते कद का अंदाजा उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाले कार्यकर्ताओं की टोली से लगाया जाता है। इसे अस्वाभाविक भी नहीं माना जाता। मगर जब साठ-सत्तर की उम्र के कार्यकर्ता नए उभरते कद के युवा नेता के चरण छूने लगें तो यह असहज तो दिखता ही है। पर बात तब ज्यादा अजीब लगती है जब ऐसे उभरते युवा नेता चरण छूने की इस सियासत को अपने बढ़ते कद का आईना मानने लगते हैं। कांग्रेस मुख्यालय में कुछ ऐसा ही दृश्य तब नजर आया जब पार्टी कार्यकर्ता एआइसीसी के गुजरात प्रभारी के चरण छूने के लिए होड़ करते दिखे। मगर इस युवा नेता ने अपने से कहीं ज्यादा उम्रदराज कार्यकर्ताओं को चरण छूने से रोकना मुनासिब नहीं समझा। काबिले गौर यह है कि राहुल गांधी पार्टी में चरण छूकर आगे बढ़ने की सियासी संस्कृति के खिलाफ आवाज मुखर करते रहे हैं, परंतु जब उनकी टीम के नेता ही इसे अपने बढ़ते कद के रूप में देखने लगेंगे तो भला ऐसे हालात क्यों बदलेंगे?

ट्वीट-ट्वीट

गांधी के जीवनीकार के रूप में मैं शब्दों से अपनी लड़ाई लड़ता हूं, हथियारों से नहीं। मैं कहीं भी, किसी से भी वाद-संवाद करूंगा और मुझे किसी का डर नहीं। यह अहमदाबाद के अच्छे लोगों की भलाई के लिए ही है कि वे इसे संभव और व्यावहारिक बनाएं कि मैं वहां आकर व्याख्यान दे सकूं।

रामचंद्र गुहा@Ram_Guha

आपकी आपत्तियां यथार्थ से परे हैं। सच यही है कि जहां आपके वामपंथी क्लब की शिरकत नहीं होती वहां आप जा ही नहीं सकते। आपमें इतना भी शिष्टाचार नहीं कि जयपुर डायलॉग के आमंत्रण पर कोई प्रतिक्रिया देते। कम से कम रोमिला थापर ने ई-मेल के जरिये तो कह दिया था कि वह इसमें भाग नहीं लेंगी।

संजय दीक्षित@Sanjay_Dixit

जापान में भारतीय समुदाय के साथ। जापान ने प्रगति की उच्चतम स्थिति प्राप्त कर यह भी दिखाया कि किसी भी देश की उन्नति में उसकी संस्कृति, सभ्यता, मूल्य, भाषा और परंपराओं का बहुत महत्व होता है।

किरण रिजिजू@KirenRijiju

हमने तो सुना था कि आसिफा के इंसाफ की लड़ाई के लिए लोगों ने काफी मदद कर दी थी। फिर उसके परिवार को इंसाफ की लड़ाई के लिए अपने मवेशी क्यों बेचने पड़े?

रोहित सरदाना@sardanarohit

जनपथ

बापू किस घर कर दिया लाकर मेरा ब्याह,
साजन भी 'बुड़बक' मिला हुई जिंदगी स्याह।
हुई जिंदगी स्याह आह! कैसी दुश्वारी,
है पूरा परिवार यहां तो भ्रष्टाचारी।
रक्खा कब तक जाय इमोशन पर अब काबू,
इस दोजख से जल्द निकालो हमको बापू!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। **वर्ष 29 अंक 110**